have already been provided safe drinking water from this scheme. Remaining villages are likely to be covered by the end of June, 1992.

(e) No financial assistance is given to the affected villagers. Safe drinking water facilities are provided free of cost either through alternative safe sources or through defluoridation plants.

विदेशी सहायता वाली पेयजल परियोजनायें

1313. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी पेय जल परियोजनाएं विदेशी कर्ज/सहायता से चल रही है ; और

(ख) इन परियोजनाओं से कितने व्यक्ति, लाभान्वित हो रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच पटेल) : (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश राज्यों में इंग्लैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी और विश्व बैंक की सहायता से 32 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) इन परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे लोगों के बारे में सूचना फिलहाल केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है । इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शीत भण्डारण सुविधा

1314. **कुमारी आलिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फेल, सब्जियां और बाजरे के लिए पर्याप्त शीत भण्डारण सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फल, सब्जियों और बाजरे के लिए शीत भंडारण सुविधाओं की अपर्याप्तता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

मध्य प्रदेश में 116 शीत भण्डागार हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 222599 मीटरी टन है ।

उत्तर प्रदेश में राज्य शीत भण्डागार अधिनियम के अन्तर्गत शीत भाण्डागारों का विनियमन किया जाता है । उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, राज्य में 906 शीत भाण्डागार हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 3554310 मीटरी टन है ।

Issue of Pass-Book to Agricultural Land-Holders/Tillers

1315. SHRI SHABBIR AHMED SALARIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pass-books have not been issued to agricultural land-holders and tenants of agricultural land in J & K although the same have been got printed ;

(b) whether it is a fact that such pass-books have been issued in many other States ; and

(c) if so, what steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

(b) Pass-books have been issued in some States like Andhra Pradesh, Gujarat Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Sikkim and Tamil Nadu.

(c) A Conference of Revenue Ministers was held on the 14th March, 1992. In this Conference it was recommended that all States should take legal and administrative action within a time frame of 3 to 6 months to ensure that land holders are given Patta Pass-books. The State Governments have been advised accordingly.

विकास परियोजनाओं में ग्रामीण लोगों का योगदान

1316. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामीण विकास परिषद के माध्यम से निष्पादित की जा रही विकास परियोजनाओं में ग्रामीण लोगों का कितने प्रतिशत योगदान है ;

(ख) ग्रामीण लोगों को अनुसन्धान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या-क्या विभिन्न योजनाएं हैं; ग्रामीण लोगों द्वारा अब तक कितने पेटेंटों अथवा प्रतिलिप्यधिकारों का दावा किया है और उनका वार्षिक औसत कितना है ;

(ग) ग्रामीण लोगों द्वारा और अधिक अनुसन्धान करवाने और उनके लिए और अधिक प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करवाने की समयबद्ध योजना क्या है ; और

(घ) सभी ग्रामीण विकास पत्रिकाओं के नामों को हिन्दी में बदलने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि इस समय इन सभी पत्रिकाओं के नाम अंग्रेजी में हैं और बहुत अटपटे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार को ग्रामीण विकास परिषद तथा उसके माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (घ) ग्रामीण लोगों द्वारा अनुसंधान किए जाने के बारे में कोई योजना नहीं है । तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, आपरेशन रिसर्च, ऑनफार्म रिसर्च तथा "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम (लैब टू लैंड प्रोग्राम) की मार्फत अनुसंधान प्रौद्योगिकी के परिणाम को किसानों तक पहुंचाया जाता है; ग्रामीण लोगों द्वारा पेटेंटों अथवा प्रतिलिप्याधिकारों का दावा किए जाने के बारे में कोई विशेष योजना नहीं है ।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय दो मासिक प्रकाशन–कुरुक्षेत्र और ग्रामीण विकास न्यूजलेटर प्रकाशित करता है । ग्रामीण जनसंख्या के काफी बड़े वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उददेश्य से ये दोनों प्रकाशन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों के नामों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Villages not covered by Drinking Water Mission

1317. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Drinking Water Mission has issued a Statement that only 4,346 villages are left to be covered by their mission ;

(b) how many villages were actually covered by the Drinking Water Mission; and

(c) what are the details of amount spent by the mission so far, giving yearly figures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) 3326 'No Source' problem villages remained to be provided safe drinking water facilities as on 1-4-92.